

कैलाश विजयवर्गीय

वी.

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य

(2021 का आपराधिक अपील सं. 1581 आदि)

04 मई, 2023

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 156 (3) - संज्ञेय मामले की जाँच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति आवेदन यू/एस। 156 (3) पीड़ित द्वारा-शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं पर बलात्कार का आरोप लगाया; और शिकायत को प्राथमिकी के रूप में लेते हुए मामले की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की-उक्त आवेदन दायर करने से पहले, पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज कीं, जिन्होंने जांच की और पाया कि शिकायत दर्ज करने में दो साल की देरी हुई थी और उसी आवेदन को खारिज करने से इनकार कर दिया। 156 (3) उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात मजिस्ट्रेट पुनरीक्षण आवेदन द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करते हुए, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट वह चरण आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका-मजिस्ट्रेट को आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश जारी करना। 156 (3) रिमांड पर मजिस्ट्रेट ने यू/एस आदेश पारित किया। 156 (3) एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: यह अस्वीकार्य है और

आरोप के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने और निर्धारित करने के लिए कानून के विपरीत

तथ्यों को आधारहीन बताते हुए, आगे की जांच और जांच के बिना-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को भेजने में सही था-मजिस्ट्रेट,

बाद का आदेश यू/एस। 156 (3) एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देना, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और निर्देशों को गलत तरीके से पढ़ना-मजिस्ट्रेट

जाँच करना, अपने विवेकपूर्ण दिमाग को लागू करना और फिर व्यायाम करना आवश्यक है

यू/एस द्वारा निर्देश जारी करने या नहीं करने का विवेकाधिकार। 156 (3) या क्या उसे संज्ञान लेना चाहिए और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। 202 - वह पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकता है-इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा मामले को मजिस्ट्रेट को वापस भेजने के आदेश को बरकरार रखा जाता है-मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर पारित आदेश, प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जाता है ताकि वह अपने न्यायिक दिमाग को लागू कर सके और यू/एस के विवेकाधिकार का प्रयोग कर सके। 156 (3) या यू/एस का संज्ञान लेना। 202 कोड से।

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएस। 156 (3) और 202-मजिस्ट्रेट की यू/एस के तहत पूर्व-संज्ञान पर जांच का निर्देश देने की शक्ति। 156 (3) और संज्ञान के बाद के चरण यू/एस. एस. 200-210 - - - आयोजित के बीच अंतर: पावर यू / s.156 (3) का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा यू/एस का संज्ञान लेने से पहले किया जाना है। 190

- एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तो मजिस्ट्रेट को अपनी शक्तियों का सहारा लेने का विवेकाधिकार होता है। 202 - मजिस्ट्रेट एक बहुत ही सीमित शक्ति का प्रयोग करता है s.156 (3) जबकि, u/s। 202 , मजिस्ट्रेट की गई शिकायत की सच्चाई का विश्लेषण कर सकता है और

इस बात की सराहना करें कि क्या आगे बढ़ने के लिए कोई आधार हैं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत शक्ति का आह्वान व्यापक है जैसा कि प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में माना गया है, फिर भी वहाँ है

ऐसी सीमाएँ हैं जिनके भीतर मजिस्ट्रेट को कार्य करना चाहिए। जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, तो उसे अपना हाथ रखना चाहिए, एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने और आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए इसे जांच एजेंसी पर छोड़ देना चाहिए। मजिस्ट्रेट ललिता कुमारी के मामले में अनुपात के संदर्भ में कर सकते हैं

अच्छे कारणों से प्रत्यक्ष प्रारंभिक जांच। [पैरा 22] [164-एफ-एच]

1.2 . ए में सूचना के पंजीकरण के लिए कार्यप्रणाली

संज्ञेय अपराध और अंतिम जांच पुलिस तक ही सीमित नहीं है, और धारा 156 की उप-धारा (3), कानूनी शर्तों के अधीन, मजिस्ट्रेट को सुधार करने की शक्ति देती है। धारा 190 के तहत जांच का आदेश देने के लिए सशक्त

संज्ञेय अपराध। दो अलग-अलग शक्तियाँ, अर्थात् पुलिस और मजिस्ट्रेट, जो ऊपर बताए गए कोड के तहत अलग-अलग कार्यों और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, पूरी तरह से निहित नहीं हैं। मजिस्ट्रेट की जांच का निर्देश देने की शक्ति संहिता के दो अंगों के तहत आती है: एक धारा 156 (3) के तहत पूर्व संज्ञान चरण है, और दूसरा अध्याय XIV के तहत संज्ञान पर है। कार्यवाही ' ; धारा 190-199) अध्याय XV (' मजिस्ट्रेटों को शिकायतें ' ; धारा 200-210) के साथ पढ़ी जाती है। ये दोनों शक्तियाँ अलग-अलग हैं और दोनों के बीच एक प्रक्रियात्मक अंतर भी है। [पैरा 23,24] [165-बी-डी] कैलाश विजयवर्गीय बनाम।

1.4 तत्काल मामले में, प्रारंभिक पूछताछ का निष्कर्ष है कि 2018 के बीच पुलिस को किए गए संचार में 2020 , 29 नवंबर 2018 को बलात्कार होने का कोई आरोप नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए कोई तार्किक और संतोषजनक विवरण देने में विफल रहा था। आरोपी का कहना है कि शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और तीसरे व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले को देखते हुए आरोपी पर दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई है। साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता/मुखबिर ने उन व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि के कई आरोप लगाए हैं जिनके साथ वह परिचित थी और

काम करते हैं। शिकायतकर्ता/मुखबिर ने अपराधियों के रूप में नामित व्यक्तियों के हाथों धमकी और उत्पीड़न का अनुरोध किया है। जो देरी के आधार और कारण के रूप में प्रभाव और शक्ति के लोग हैं। वह दलील देती है कि संहिता की धारा 468 में निर्धारित सीमा की अवधि तीन साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध पर लागू नहीं होती है। शिकायत करने में देरी के सवाल की जांच करते समय, अदालतों को इस तथ्य पर जीवित रहना चाहिए कि एक महिला के लिए आगे आना और बलात्कार या यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बयान देना मुश्किल है। [पारस 33 और 34] [171-बी-एफ] [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.5 प्रत्येक आपराधिक मामला, यह कहा जाता है, खोज की यात्रा है

जिसमें सत्य खोज है। न्यायिक प्रणाली की शुरुआत से ही, यह स्वीकार किया गया है कि सत्य की खोज, पुष्टि और स्थापना न्याय की अदालतों के अस्तित्व में अंतर्निहित प्राथमिक उद्देश्य हैं। लेकिन सर्वोच्चता

सत्य को परिभाषित करने की तुलना में दावा करना आसान है। अक्सर यह कार्य तब कठिन हो जाता है जब विरोधाभासी तथ्यात्मक स्थितियों का विधिवत समर्थन किया जाता है और शपथ पर पुष्टि की जाती है। प्रतिकूल प्रणालियों में, सच्चाई का पता लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाओं और साक्ष्य के नियमों के अनुपालन की आवश्यकता होती है, और आरोपों और जवाबी आरोपों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक अन्वेषक के रूप में कार्य करने में निर्णायक की भूमिका को सीमित करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि सबूत और सामग्री को संहिताबद्ध प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार रखा और जांचा नहीं जाता है। फिर भी यह माना जाता है कि संघर्ष

तथ्यों को बाहर निकालने के लिए विरोधियों की गणना करना सबसे अच्छा है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई प्रणाली में, औपचारिक कानूनी सच्चाई के न्यायिक निष्कर्षों को होना चाहिए

मूल सत्य के साथ मेल खाते हैं। यह तब हो सकता है जब प्रतियोगियों द्वारा बताए गए तथ्यों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुशलता से खोजा जाता है। कानून के दुरुपयोग की जांच, यदि संभव हो, तो बहुत हद तक की जानी चाहिए, भले ही यह संभव हो और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भी। [पैरा 35] [171-एफ-एच; 172-ए-बी]

1.6 . जब मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जाती है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक है एक आदेश पारित करना जिसके द्वारा विचार किया गया हो

धारा 156 (3)। दूसरा शपथ पर शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाह की जांच का निर्देश देना और धारा 202 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से आगे बढ़ना है। धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पुलिस को जांच की अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आकस्मिक अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति में है।

धारा 156 (1)। हालांकि, एक बार मजिस्ट्रेट ने ले लिया है

संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेते हुए, वह पुलिस द्वारा जांच के लिए नहीं कह सकता है। संज्ञान लिए जाने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट कोई जांच चाहता है, तो यह धारा 202 के तहत होगा, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है और किसी झूठी या परेशान करने वाली शिकायत में प्रक्रिया को जारी करने से रोकना है। इसलिए इस तरह की जांच यह पता लगाने के लिए प्रदान की जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। [पैरा 36] [173-बी-डी] कैलाश विजयवर्गीय बनाम।

राजलक्ष्मी चौधरी

और अन्य

1.7 आरोपों के गुण-दोष और मजिस्ट्रेट को किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, इस सवाल पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह है -

एक पहलू जिस पर मजिस्ट्रेट को पहले विवेकपूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। जो अस्वीकार्य और कानून के विपरीत है वह आरोपों के गुण-दोष के आधार पर निर्णय है और

आगे की जांच और जांच के बिना तथ्यों को आधारहीन के रूप में निर्धारित करना। इसलिए, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजने में सही किया। [पैरा 37] [173-ई-एफ]

1.8 मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने गलत पढ़ा है।

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश और निर्देश। मजिस्ट्रेट से जाँच करने, अपने विवेकपूर्ण दिमाग को लागू करने और फिर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।

धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करना है या नहीं या क्या उसे संज्ञान लेना चाहिए और धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वह प्रारंभिक जाँच का निर्देश भी दे सकता है।

ललिता कुमारी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस। [पैरा 38] [173-जी]

1.9 अभियुक्त को समन जारी होने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, कानून देता है

न्यायालय और यह न्यायालय। उनके लिए निष्पक्ष होने के लिए, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए कागजातों और दस्तावेजों की प्रतियां भी भेजी जाएंगी और मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में रखी जाएंगी, जो इसके बाद मामले की जांच और विचार करेंगे। हालांकि, शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता और सामग्री पर सवाल उठाने का अधिकार होगा। [पैरा 39] [174-ए-सी]

1.10 . इसे ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय की पुष्टि करते हुए

और उच्च न्यायालय द्वारा मामले को मजिस्ट्रेट को वापस भेजने का आदेश पारित किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर पारित बाद के आदेश को दरकिनारा कर दिया गया है और मामले को [2023] 6 एस में वापस भेज दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट अपनी न्यायिक बुद्धि की जांच करेगा और उसे लागू करेगा और विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा कि धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करना है या नहीं या क्या वह संज्ञान ले सकता है और धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन कर सकता है। वह ललिता कुमारी के मामले में इस सी द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकता है। [पैरा 40] [174-डी-ई]

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713-अनुसरण किया गया।

प्रियंका श्रीवास्तव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6

एससीसी 287: [2015] 4 एस. सी. आर. 108-पर निर्भर।

मुकल रॉय बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल. 4861 ; मकसूद सैय्यद बनाम। गुजरात राज्य

गुजरात (2015) 6 एस. सी. सी. 439: [2015] 5 एस. सी. आर. 283; सुरेश कांकरा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (आपराधिक अपील नहीं. 52/2022,07.01.2022 पर तय किया गया); श्रीनिवास

गुंडलुरी और अन्य बनाम। सेपको इलेक्ट्रिक पावर

निर्माण निगम (2010) 8 एससीसी 206; अंजू

चौधरी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 एस. सी. सी. 384: [2012] 13 एस. सी. आर. 901; सीमा शुल्क सहायक कलेक्टर, बॉम्बे बनाम। एल. आर. मेलवानी एयर 1970 एस. सी. 962: [1969] एस. सी. आर. 438; कृष्ण लाल चावला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 5 एस. सी. सी. 435; अभिनंदन झा बनाम। दिनेश मिश्रा ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 117 [1967] एस. सी. आर. 668; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, (1992) 1 पूरक एस. सी. सी. 335: [1990] 3 पूरक एस. सी. आर. 259; मो. यूसुफ बनाम। अफाक जहां (श्रीमती) और एक अन्य (2006) 1 एस. सी. सी. 627: [2006] 1 एससीआर 1; एचडीएफसी सिक्क्योरिटीज लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2017) 1 एससीसी 640: [2016] 8 एस. सी. आर. 968; चंद्र देव सिंह बनाम। प्रकाश चंद्र बोस उपनाम चाबी बोस और एक अन्य

ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1430: [1964] एस. सी. आर. 639; जसराज इंदर सिंह बनाम। हेमराज मुल्तानचंद (1977) 2 एस. सी. सी. 155: [1977] 2 एससीआर 973; गोपाल दास सिंधी और अन्य बनाम। असम राज्य और एक अन्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 986; सुरेश चंद्र जैन बनाम एम. पी. राज्य और एक अन्य (2001) 2 एस. सी. सी. कैलाश विजयवर्गीय बनाम।

राजलक्ष्मी चौधू

और अन्य

628 [2001] 1 एस. सी. आर. 257; मोना पंवार बनाम उच्च न्यायालय
अपने पंजीयक के माध्यम से इलाहाबाद की न्यायपालिका और
अन्य (2011) 3 एस. सी. सी. 496: [2011] 2 एससीआर 413-संदर्भित
को।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 9 एससीआर 1113

पैरा 3.6

संदर्भित किया गया है

[2013] 9 एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.6

[2015] 5 एससीआर 283

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.6

[2012] 13 एससीआर 901

पैरा 4.2

संदर्भित किया गया है

[1969] एससीआर 438

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.7

(2021) 5 एससीसी 435

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1967] एससीआर 668

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

[2013] 14 एससीआर 713

पैरा

22,27,

पीछा किया।

[2015] 4 एससीआर 108

पर भरोसा किया।

पैरा

22,27

[2006] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2016] 8 एससीआर 968

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1964] एस. सी. आर. 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1977] 2 एससीआर 973

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2001] 1 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2011] 2 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: क्रिमिनल एपिया

1581 2021 से।

उच्च न्यायालय के 01.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के सी. आर. आर. संख्या 92 में कलकत्ता में।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1582 और 2021 का 1583।

महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पी. एस. पटवालिया, सीनियर ए.

कबीर शंकर बोस, अमित मिश्रा, अमित तिवारी, कनिका सिन सुश्री मुग्दा पांडे, सुरजेन्दु शंकर दास, सुश्री एनी एम सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री कनिका सिंघल, धीरज त्रिवेदी, [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चौधरी, अरविंद गुप्ता, सुश्री सौम्या कपूर, सिद्धांत यादव, नचिकेता जोशी, अमित तिवारी, संतोष कुमार, प्रणीत प्रणव, वेदांश आनंद, आयुष आनंद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। आर. बसंत, बिकाश रंजन भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, अक्षय सहाय, सायनदीप पहाड़ी, मेसर्स। पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी, रउफ रहीम, अली असगर रहीम, अरविंद सी., एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एम. आर. शाह, जे.

1. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.10.2021 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 92/2021, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 इसमें-मूल शिकायतकर्ता (पीडित) और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर (संक्षेप में, 'विद्वान सी. जे. एम.')

द्वारा पारित दिनांक 12.11.2020 के आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिवादी नं. 1 इसमें-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता/Cr.PC) की धारा 156 (3) के तहत मूल शिकायतकर्ता मूल प्रतिवादी संख्या। 2 4 तक

(कथित अभियुक्त) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों का नेतृत्व करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

वह उत्तरदाता नहीं। 1 यहाँ-मूल शिकायतकर्ता ने धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत विद्वान सीजेएम की अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया गया कि सभी तीन अपीलकर्ताओं द्वारा लगभग 5 बजे 29.11.2018 पर उसके साथ बलात्कार किया गया था: 00 मूल अभियुक्त नं. के निवास पर अपराह्न। 3 - कैलाश विजयवर्गीय, जब वह

उनके द्वारा दायर उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 2018 के एक अन्य अपराध संख्या 1 पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कि शिकायत को एफ. आई. आर. मानने के बाद भवानीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मामले की जांच शुरू करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

2.1 विद्वान सीजेएम के समक्ष शिकायत में शिकायतकर्ता की ओर से यह मामला था कि वह राज्य समिति की सदस्य थी

पश्चिम बंगाल राज्य में भारतीय जनता पार्टी। सक्रिय राजनीति में शामिल एक व्यक्ति के रूप में, वह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के नेताओं से परिचित हैं। बलात्कार के आरोप पर, उसने एक अमलेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ बेहाला (महिला) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत धारा 417/376/406/313/कैलाश विजयवर्गीय बनाम के तहत मामला संख्या 01/2018 दिनांक 31/08/2018 के रूप में दर्ज की गई थी।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

120 बी आई. पी. सी. उक्त मामले की जांच के परिणामस्वरूप उपरोक्त अमलेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। यह आगे आरोप लगाया गया कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद से, वह थी

अपीलार्थियों, अर्थात् प्रदीप जोशी, जिष्णु बसु और द्वारा दबाव डाला गया

गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अपीलार्थियों ने उसे धमकी दी कि अगर वह उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाती है तो उसके बेटे को भी मार दिया जाएगा। यह आगे आरोप लगाया गया कि बाद में भी वह थी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक यातना के अधीन और उसने आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई, जैसे कि सरसुना पी. एस. केस नंबर <आई. डी. 2 आई. पी. सी. की धारा 341/506 (ii)/34 और बोलपुर पी. एस. केस नंबर <आई. डी. 5 आई. पी. सी. की धारा 341/323/325 506/34 के तहत। यह था।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया और इसलिए कहा गया कि 29.11.2018 की घटना पर, उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे ऐसी शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन वे भी प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने बेहाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को 14.08.2020 पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से 9.8.2018 पर कथित बलात्कार के बारे में सूचित किया।

2.2 उन्होंने डी. सी. पी. (साउथ डिवीजन), 34, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता के समक्ष 5.10.2020 पर शिकायत दर्ज कराई। उनके अनुसार, उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन, यानी पी. एस. भवानीपुर में 27.10.2020 पर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने 04.11.2020 पर पुलिस उपायुक्त के पास एक और शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, उपरोक्त [2023] 6 एस. सी. आर. के बावजूद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 2 पर उसके साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाते हुए विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें, एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई है और कोई जांच नहीं की गई है और इसलिए उसने आई. डी. 3 पर धारा 156 (3) के तहत विद्वान सी. जे. एम., अलीपुर की अदालत में एक आवेदन दायर किया और संबंधित पुलिस अधिकारी को एफ. आई. आर. दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

2.3 कि विद्वान सी. जे. एम. ने दिनांक 12.11.2020 के एक विस्तृत आदेश द्वारा और ठोस कारण देने के बाद उक्त आवेदन को खारिज कर दिया

धारा 156 (3) Cr.P.C।

2.4 विद्वान सीजेएम द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता द्वारा दायर धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज करते हुए, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन को आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 92/2021 के रूप में प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से ललिता कुमारी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए धारा 156 (3) के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य ने (2014) 2 एस. सी. सी. 1 में प्रतिवेदन दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, संज्ञेय अपराध से संबंधित मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के मामले में पुलिस प्राधिकरण के पास आरोपों की सच्चाई को सत्यापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए एक मजिस्ट्रेट आरोपों की सच्चाई और सच्चाई को सत्यापित नहीं कर सकता है। धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन में निहित है और इसलिए विद्वान सी. जे. एम. ने आरोपों की सच्चाई और सच्चाई में प्रवेश करते हुए, ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत काम किया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विद्वान सीजेएम को धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए था कि शिकायत दर्ज करने में दो साल की देरी हुई थी, जिस पहलू पर केवल मुकदमे के समय ही विचार किया जा सकता है।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान सीजेएम द्वारा दिनांकित 12.11.2020 द्वारा पारित आदेश को रद्द और रद्द करते हुए और मामले को विद्वान सीजेएम को धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए भेजते हुए. विवादित निर्णय और आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करते हुए, मूल प्रतिवादियों-कथित अभियुक्तों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

कैलाच विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

3. एस/श्री महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह और पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी-अभियुक्त ने जोर देकर कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत को खारिज करते हुए विद्वान सी. जे. एम. द्वारा पारित सुविचारित आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने में गंभीर त्रुटि की।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि विद्वान सीजेएम ने धारा 156 (3) के तहत आवेदन को खारिज कर दिया।

Cr.P.C. आवेदन में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता की पुष्टि करने पर, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित घटना की तारीख के बाद लगभग दो साल की देरी हुई थी, जिसका वर्णन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान सी. जे. एम. आवेदन में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था, जब इस तरह के गंभीर आरोप कथित घटना की तारीख के लगभग दो साल बाद लगाए गए थे और इसके बीच में हालांकि कई अन्य शिकायतें थीं। अभियुक्त और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज, किसी भी समय, 29.11.2018 पर बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

सीजेएम, उच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया है और/या विचार किया है और/या लागू किया है। 3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह देखने में भौतिक रूप से गलती की है कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर विचार करते समय, मजिस्ट्रेट के पास आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में की गई टिप्पणियां कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर विचार करते समय, मजिस्ट्रेट को आवेदन में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता को प्रथम दृष्टया सत्यापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्रियंका [2023] 6 एस. सी. आर. के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बिल्कुल विपरीत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीवास्तव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 287 में सूचित किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय के विपरीत भी है। पश्चिम बंगाल राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल. 4861 , स्पष्ट रूप से

प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) में फैसले के बाद।

3.6 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इन मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है -

मकसूद सैय्यद बनाम। गुजरात राज्य, (2008) 5 एस. सी. सी. 668 में सूचित; अनिल कुमार बनाम। एम. के. अयप्पा, (2013) 10 एस. सी. सी. 705 में सूचित; और रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य, रिपोर्ट किया गया

(2015) 6 एस. सी. सी. 439 में और सुरेश कांकरा बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (आपराधिक अपील सं. 52/2022, ने 07.01.2022 पर निर्णय लिया), उनके इस निवेदन के समर्थन में कि मजिस्ट्रेट आवेदन में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था, विशेष रूप से जब कथित घटना की तारीख के दो साल बाद बलात्कार का ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया था।

3.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने मुकुल राय (उपरोक्त) के मामले में समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखना सही और/या उचित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश की राय थी कि मुकुल राय (उपरोक्त) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही कानून नहीं है, तो उस मामले में औचित्य की मांग है कि विद्वत एकल न्यायाधीश को मामले को विपरीत दृष्टिकोण लेने के बजाय बड़ी पीठ को भेजना चाहिए था।

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी विद्वान एकल न्यायाधीश

इस बात की सराहना की जानी चाहिए थी कि मुकुल राय (ऊपर) के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) के मामले में इस माननीय न्यायालय के फैसले का पालन कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए भी, विद्वान एकल न्यायाधीश को ऐसा नहीं होना चाहिए

एक विपरीत दृष्टिकोण लिया।

3.9 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में एस. एच. ओ. ने भी अक्टूबर, 2020 के महीने में शिकायत प्राप्त करने के बाद इस अदालत द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच की और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।

कैलाश विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

3.10 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

संबंधित अपीलकर्ताओं ने हमें अपीलकर्ताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को 30.11.2018, यानी कथित घटना के अगले दिन मार्च, 2020 तक भेजे गए ईमेल और संदेशों की संख्या के बारे में बताया है। यह है।

प्रस्तुत किया कि यदि उसने 29.11.2018 पर बलात्कार किया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था, उस मामले में, बाद में उसके पास अपीलार्थी-कैलाश विजयवर्गीय को ईमेल और संदेश भेजने का कोई कारण नहीं था।

3.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 29.11.2018 और अक्टूबर, 2020 के बीच, शिकायतकर्ता ने विभिन्न पुलिस के समक्ष विभिन्न शिकायतें दर्ज कीं।

अभियुक्तों के खिलाफ ही मुकदमे। पहली शिकायत 12.12.2019 (सरसुना मामला) पर दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह अपीलार्थी से मिली थी, हालाँकि, शिकायत में बलात्कार की कथित घटना का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्राथमिकी में केवल आरोप थे कि उन्हें पिछले वर्ष नवंबर 2018 में शीर्ष स्तर के नेताओं द्वारा 4 बार बुलाया गया था और हर बार उन्होंने उन्हें 4 से 5 घंटे के लिए बंद कर दिया और मामले को वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त एफ. आई. आर. एफ. आई. आर. सं. 131/2019 के रूप में दर्ज की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि उपरोक्त मामले में 16.06.2020 दिनांकित समापन रिपोर्ट दायर की गई थी।

3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद एक अन्य शिकायत दिनांक 6.2.2020 दर्ज की गई थी, हालाँकि, किसी विशेष का कोई उल्लेख नहीं था। कथित बलात्कार की घटना की तारीख। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद एक और शिकायत 12.03.2020 पर दर्ज की गई थी जिसमें उसने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया था।

कथित बलात्कार की घटना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बलात्कार की कथित घटना के दो साल की अवधि के बाद, शिकायतकर्ता ने दिनांकित शिकायत दर्ज कराई

27.10.2020 जिसमें पहली बार उसने कहा कि अमलेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ 2018 का मामला वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाने के लिए, अपीलकर्ताओं ने उसे अपीलार्थी नं. 1 - कैलाश विजयवर्गीय ने 29.11.2018 पर उसके साथ बलात्कार किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

विद्वान सी. जे. एम. ने ठीक ही कहा कि चूंकि कथित अपराध के खिलाफ शिकायत करने में दो साल की अस्पष्ट और अत्यधिक देरी हुई थी, इसलिए यह धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन में निहित आरोपों की सच्चाई और सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है।

3.13 यह आगे संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश पारित करते समय दिनांकित

12.11.2020, विद्वान सी. जे. एम. ने इस बात को उजागर करने के लिए कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं कि कथित अपराध के खिलाफ पहली पुलिस शिकायत करने में अत्यधिक देरी हुई थी और यह कि पर्याप्त [2023] 6 एस. सी. आर. मौजूद थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 156 (3) के तहत आवेदन में निहित आरोपों की सच्चाई और सत्यता के बारे में संदेह पैदा करने के लिए विसंगतियां। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पहले, विद्वान सीजेएम ने पाया कि शिकायतकर्ता के अनुसार कथित अपराध 29.11.2018 पर हुआ, हालाँकि, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का प्रयास पहली बार केवल 27.10.2020 पर किया गया था।

जिस तारीख को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। यह कथित अपराध की तारीख से लगभग दो साल के अंतराल के बाद हुआ था।

3.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद विद्वान सीजेएम ने आगे उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने धारा 156 (3) के तहत अपने आवेदन में कहा है कि उसने आरोपी व्यक्तियों और उनके आदमियों के खिलाफ उस पर किए गए शारीरिक हमलों के लिए विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें की हैं, हालांकि, ऐसी किसी भी शिकायत में बलात्कार के कथित अपराध का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए, विद्वान सीजेएम ने नोट किया कि गलत होने की संभावना

निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब एक ही शिकायतकर्ता ने उस अवधि में एक ही आरोपी के खिलाफ कई अन्य शिकायतें कीं जिसमें 29.11.2018 पर बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

3.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान सी. जे. एम. ने आगे यह भी देखा कि शिकायतकर्ता ने बेहाला पुलिस स्टेशन में दिनांक 14.08.2020 में अपनी शिकायत में अपीलकर्ताओं में से एक कैलाश पर आरोप लगाया था।

विजयवर्गीय ने 09.08.2018 पर होटल पीयरलेस इन में उसके साथ बलात्कार किया, हालांकि, विद्वान सी. जे. एम. को धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत अपने आवेदन में ऐसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिला। विद्वान सी. जे. एम. ने आगे कहा कि बेहाला पुलिस स्टेशन मामला संख्या 01/2018 अमलेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ है।

और अन्य को 31.08.2018 पर दर्ज किया गया था, जो कि होटल पीयरलेस इन में कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित बलात्कार के बहुत बाद था, हालाँकि, बेहाला पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत में भी ऐसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए, शिकायत करने में लगभग दो साल की अस्पष्टीकृत देरी के साथ-साथ कई विसंगतियों पर विचार करते हुए विद्वान सीजेएम ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं और इसलिए शिकायतकर्ता के धारा 156 (3) आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया।

3.16 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, विद्वान सीजेएम ने शिकायतकर्ता द्वारा पूरी तरह से देरी के लिए स्पष्टीकरण पाया।

असंतोषजनक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार के मामले में देरी हमेशा घातक नहीं होती है, विशेष रूप से यदि पर्याप्त रूप से समझाया गया है, हालांकि, कैलाश विजयवर्गीय बनाम के स्पष्टीकरण में कम से कम कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

विलम्ब। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बलात्कार के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में, एक देरी

हालाँकि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया गया, लेकिन उस तारीख से उसके आचरण की जांच की गई। धारा 156 (3) आवेदन दायर होने तक कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया और पाया गया कि उसका आचरण देरी के लिए उसके स्पष्टीकरण का खंडन करता है। कि वह एक डरपोक पीड़ित नहीं थी क्योंकि वह एक अनुभवी सामाजिक/राजनीतिक थी

कर्मचारी; बलात्कार सहित एफ. आई. आर. दर्ज करने का इतिहास था; पहले अन्य अपराधों के लिए तत्काल मामले में आरोपी के खिलाफ एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया था और

3.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जैसा कि इस न्यायालय ने ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जब पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में अधिकारी के पास आरोपों की सत्यता और सच्चाई को सत्यापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कैसे एक मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत में आरोपों की सच्चाई को सत्यापित कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पुलिस तक ही सीमित रहेंगे और धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट पर लागू नहीं होंगे।

3.18 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बाद का आचरण भी

शिकायतकर्ता का हिस्सा उसकी विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता को इस गंभीर संदेह का एहसास होने के बाद कि उसकी देरी से की गई शिकायत उसके आरोपों की सच्चाई पर निर्भर करती है

पूरी तरह से, इस अदालत के समक्ष जवाबी हलफनामे में, उन्होंने [2023] 6 एस. सी. आर. पर कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शपथ ली और अब एक मामला सामने आया है कि उसने वास्तव में अगले ही दिन 11 बजे शिकायत दर्ज करके 29.11.2018 पर कथित बलात्कार की घटना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी: 00 a.m.at बेहाला पुलिस स्टेशन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 156 (3) के तहत आवेदन में और/या यहां तक कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायतों में भी उसका मामला नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी न्यायालय को सूचित किया है कि शिकायत दर्ज किए जाने का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार शिकायतकर्ता ने केवल देरी से बाहर निकलने और इस तथ्य को सामने लाने के लिए कि अक्टूबर, 2020 तक, 29.11.2018 पर बलात्कार की कथित घटना के संबंध में उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई थी, इस अदालत के समक्ष शपथ पर गलत बयान दिया है।

3.19 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला प्रक्रिया के दुरुपयोग और कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह है।

प्रस्तुत किया कि बलात्कार का आरोप प्रथम दृष्टया गलत है और इन झूठे आरोपों के बहाने आरोपी से जबरन वसूली या ब्लैकमेल करने के इरादे से बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना की तारीख से लगभग दो साल की अवधि के बाद बलात्कार का इतना गंभीर आरोप अपीलार्थियों की छवि को धूमिल करने और राजनीतिक बदला लेने और अपीलार्थियों के राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए लगाया गया है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और रद्द कर दिया जाए और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि वर्तमान कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान अपीलें इस न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, विद्वान

सीजेएम ने 08.10.2021 दिनांकित एक आदेश पारित किया है जिसमें भवानीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आवेदन को एक प्राथमिकी के रूप में मानने का निर्देश दिया गया है और विद्वान सीजेएम के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 221/2021 दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्राथमिकी उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश के परिणामस्वरूप दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, तो उस मामले में, बाद के सभी परिणामी आदेश और बाद में प्राथमिकी दर्ज करना भी योग्य है। रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

4. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने जोर देकर कहा है कि मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता और आवेदन के चरण में आरोपों की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है।

कैलाच विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है यदि वह किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) में विचार की गई प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या एक संज्ञेय

अपराध प्रकट होता है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पुलिस अधिकारी गलत तरीके से या गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करता है, तो शिकायतकर्ता के पास धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) में निर्णय मजिस्ट्रेट को इसकी विश्वसनीयता पर विचार करने का अधिकार देता है।

श्रीनिवास गुंडलुरी और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता और धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन के चरण में भी आरोपों की स्वीकार्यता। एस. ई. पी. सी. ओ. इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, (2010) 8 एस. सी. सी. 206 में रिपोर्ट किया गया; और अंजू चौधरी बनाम। (2013) 6 एस. सी. सी. 384 में रिपोर्ट की गई यू. पी. राज्य की यह याचिका कि शिकायतकर्ता की सत्यता और/या विश्वसनीयता और उठाए गए आरोपों की स्वीकार्यता को मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156 (3) के स्तर पर देखा जा सकता है, सही प्रतीत नहीं होती है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाता है

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इसलिए, धारा 154 (1) के तहत पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और पूर्व-संज्ञान स्तर पर धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा के बीच कोई बेमेल नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऐसा समझा जाता है, तो प्रियंका श्रीवास्तव में सच्चाई का परीक्षण सक्षम हो जाता है। (उपर्युक्त) केवल यह पता लगाने के लिए हो सकता है कि क्या एक संज्ञेय अपराध वास्तव में बनाया गया है या नहीं। यह एक व्याख्या प्राप्त नहीं कर सकता है, जो ललिता कुमारी (ऊपर) में संदर्भ और उक्ति से अलग है। यदि ऐसा है तो धारा 154 (1) और धारा 156 (3) Cr.P.C के बीच बेमेल होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रियंका के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

श्रीवास्तव (ऊपर) इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता/गवाहों की विश्वसनीयता और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वीकार्यता की जांच कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) का ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा नहीं था।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि मजिस्ट्रेट को धारा 156 (3) के तहत संदर्भ नहीं देने का विकल्प चुनते ही शिकायत को खारिज करने की शक्तियाँ दी जाती हैं, तो यह रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत के बिना समय से पहले निष्कर्ष पर पहुँचकर शिकायत को वस्तुतः रद्द करना होगा कि शिकायतकर्ता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रभावी रूप से मजिस्ट्रेट के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का अहंकार करने के बराबर होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 156 (3) के स्तर पर, मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी जो उसे इस पर निर्णय लेने में सक्षम बनाए।

शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता या शिकायत में आरोपों की स्वीकार्यता। 4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पहले विद्वान सी. जे. एम. संबंधित पुलिस अधिकारी को पंजीकरण करने का निर्देश देने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता था।

शिकायत के रूप में एक एफ. आई. आर. एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने का विकल्प नहीं चुना है, मजिस्ट्रेट को यदि वह संतुष्ट है तो निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 156 (3) के तहत शिकायत को पुलिस स्टेशन को भेजना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैकल्पिक रूप से यदि विद्वान मजिस्ट्रेट संदर्भित नहीं करने का विकल्प चुनता है

धारा 156 (3) के तहत पुलिस को शिकायत, किसी भी मामले में, वह शिकायत को खारिज नहीं कर सकता था और इस स्तर तक आगे बढ़ गया होगा धारा 200/202 Cr.P.C. और धारा 203 या 204 Cr.P.C के तहत एक उचित निर्णय लें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.10.2020 के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए कार्रवाई की प्रार्थना करने वाली याचिका, धारा 2 (डी) Cr.P.C के तहत एक "शिकायत" के बराबर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मजिस्ट्रेट को निर्णय लेने का विवेकाधिकार है।

मामले के दिए गए तथ्यों में धारा 156 (3) या धारा 200/202 Cr.P.C के तहत जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 156 (3) का सहारा लेना भी "संहिता के तहत कार्रवाई कर रहा है" और इसलिए शिकायत नहीं है

शिकायत होना बंद हो जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 156 (3) के तहत भी कार्रवाई का अनुरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 156 (3) और धारा 200/202 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र शिकायतकर्ता की प्रार्थना/पसंद/वरीयता पर निर्भर नहीं करता है। धारा 204 Cr.P.C के तहत गवाहों और दस्तावेजों की सूची दाखिल करने की औपचारिक आवश्यकताएं संज्ञान के बाद के चरण और दाखिल करने या दाखिल करने से संबंधित हैं।

ऐसी सूची दाखिल न करने से धारा 2 (डी) Cr.P.C के तहत शिकायत के रूप में याचिका की स्थिति प्रभावित नहीं हो सकती है।

ऐसी शिकायत, मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से धारा 156 (3) के तहत एक पूर्व-संज्ञान संदर्भ बनाने या वैकल्पिक रूप से धारा 200/202 Cr.P.C के तहत एक पोस्ट-संज्ञान कार्रवाई करने का विवेकाधिकार है। यदि कोई याचिका है

धारा 2 (डी) के तहत शिकायत की परिभाषा का जवाब देते हुए, ये सभी पाठ्यक्रम खुले हैं और मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुनता है, तो कैलाश विजयवर्गीय v.

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

मजिस्ट्रेट शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकता क्योंकि वह धारा 156 (3) का सहारा लेना उचित नहीं समझता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट को अभी भी धारा 200/202 Cr.P.C के तहत जारी रहना चाहिए। और धारा 203 Cr.P.C के तहत शिकायत को खारिज करने का आदेश पारित करना चाहिए। या धारा 204 Cr.P.C के तहत एक प्रक्रिया जारी करनी चाहिए।

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान मामले में

शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह संबंधित पुलिस अधिकारी का कर्तव्य था कि वह प्राथमिकी दर्ज करे और मामले की जांच करे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि संबंधित पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने में विफल रहा, इसलिए मजिस्ट्रेट को धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देना होगा और संबंधित पुलिस अधिकारी को लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश देना होगा।

एफ. आई. आर. में

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के स्तर पर, न तो पुलिस अधिकारी और न ही मजिस्ट्रेट ने 156 (3) के स्तर पर

विस्तृत जांच/प्रारंभिक जांच करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र और/या प्राधिकरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 156 (1) और 156 (2) का पालन करने में पुलिस की विफलता के लिए मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच का निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्य और उद्देश्य प्रथम दृष्टया यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के तत्व संतुष्ट हैं।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा अनिवार्य है, जिस क्षण कोई शिकायत किसी भी संज्ञेय अपराध के तत्वों का खुलासा करती है,

आवश्यकता यह संतुष्ट करने के लिए है कि क्या एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों का खुलासा होता है संज्ञेय अपराध करना या नहीं और उससे आगे नहीं।

5.3 यह आगे उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

मूल शिकायतकर्ता की ओर से कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, की तर्कसंगतता या विश्वसनीयता एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए सूचना कोई पूर्व शर्त नहीं है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 154 Cr.P.C में "होगा" शब्द का उपयोग।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश है और शाब्दिक निर्माण का नियम लागू होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, केवल असाधारण मामलों में, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की अनुमति है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अपराध महिला के खिलाफ है और जब बलात्कार के गंभीर आरोप हैं यदि ऐसा किया जाता है, तो धारा 156 (3) आवेदन के स्तर पर आगे कोई प्रारंभिक जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है।

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) के मामले में,

पैराग्राफ 29 और 30 में, यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट एक रूढ़िवादी और नियमित तरीके से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाली प्रक्रिया जारी कर रहे थे और इसलिए इस अदालत ने कहा कि वादियों को तुच्छ याचिकाएं दायर करने से रोकने के लिए, धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए और धारा 156 (3) के तहत याचिका को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 30 में टिप्पणियाँ,

अर्थात्, उपयुक्त मामलों में, मजिस्ट्रेट सच्चाई का सत्यापन कर सकता है और टिप्पणियों के साथ आरोपों की सच्चाई को भी सत्यापित कर सकता है। पहले के पैराग्राफ में जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से आरोपों पर ध्यान देना चाहिए; घटना की तारीख और क्या कोई संज्ञेय मामला दूर से बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई निर्भरता प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) पर अपीलकर्ताओं का यह तर्क देना कि निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि एक मजिस्ट्रेट आरोपों की सत्यता को सत्यापित कर सकता है और इस तरह एक लघु परीक्षण कर सकता है, पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस स्तर पर प्रारंभिक न्यायिक अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध दूर से बनाया गया है/खुलासा किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ललिता कुमारी (ऊपर) और प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा और पढ़ा जाना चाहिए।

5.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक संशोधन अधिनियम (2013 का 13) को धारा 154 (1) Cr.P.C, धारा 173 (1 ए) Cr.P.C और धारा 166 ए, आईपीसी में संशोधन करते हुए लागू किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रक्रियात्मक आवश्यकता अनिवार्य रूप से

एफ. आई. आर. दर्ज करना धारा 154 Cr.P.C में पहले से मौजूद था, लेकिन ललिता कुमारी (ऊपर) में न्यायिक व्याख्या को एक अधिदेश होना आवश्यक था। आई. पी. सी. में धारा 166 ए को शामिल करने से शिकायत को एक संज्ञेय अपराध वाली एफ. आई. आर. के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जो लोक सेवक (पुलिस) के खिलाफ दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

इसलिए यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करे और एफ. आई. आर. के रूप में शिकायत दर्ज करना अब अपराध है।

5.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत के मामलों में भी, यह केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि है जिसे दर्ज किया जाना है और इसके तहत जांच का दायरा है।

धारा 202 केवल आरोपों की सच्चाई का पता लगाने तक ही सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं और उस स्तर पर भी जांच एक पूर्ण परीक्षण की प्रकृति में भाग नहीं लेती है जो प्रक्रिया जारी होने के बाद ही हो सकती है। अंजू चौधरी (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसले के पैराग्राफ 40 और 41 पर रिलायंस को रखा गया है।

5.7 शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्राथमिक कारण

धारा 156 (3) के तहत याचिका पर विचार नहीं करने के लिए देरी हुई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, बॉम्बे बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया है। ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 962 में एल. आर. मेलवानी ने बताया कि जिस न्यायालय के समक्ष शिकायत दायर की गई थी, वह इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता था कि इसे दायर करने में देरी हुई है। यह देखा गया है कि शिकायत दर्ज करने में देरी का सवाल हो सकता है

अंतिम निर्णय पर पहुँचने में परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन अपने आप में यह शिकायत को खारिज करने का कोई आधार नहीं देता है। यह है।

प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने उसे खुली धमकी देते हुए देरी के लिए ठोस और विशिष्ट कारण दिए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, धारा 468 तीन साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए सीमा की अवधि को कम नहीं करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए देरी के आधार पर, शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता था।

5.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वान सीजेएम को भी 156 (3) Cr.P.C के स्तर पर यह राय नहीं देनी चाहिए थी कि आरोप अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस स्तर पर न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग केवल यह पता लगाने के लिए जांच करने की सीमा तक सीमित है कि क्या कथित अपराध संज्ञेय है या नहीं और

सामग्री प्रथम दृष्टया संतुष्ट है।

5.9 प्रस्तुतियों को सारांशित करते हुए, मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि

ललिता कुमारी (ऊपर) और प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय सामंजस्यपूर्ण और [2023] 6 एस. सी. आर. के सीमित दायरे में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 156 (3) आवेदन के स्तर पर जांच, विद्वान सीजेएम ने धारा 156 (3) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की और इसलिए उच्च न्यायालय ने शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज करने और मामले की जांच करने का सही निर्देश दिया है।

5.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

अपीलें करें।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

6.1 वर्तमान कार्यवाही धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न होती है। विद्वान सीजेएम ने एक विस्तृत आदेश द्वारा और ठोस कारण बताते हुए, धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत उक्त आवेदन/शिकायत को खारिज कर दिया और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। राज्य द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन/शिकायत दर्ज करने से पहले, पुलिस अधिकारियों, अर्थात् बहेला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, डीसीपी (दक्षिण प्रभाग) और एसएचओ को शिकायतें की गई थीं। एस. एच. ओ. ने ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक जांच की और यह पता चलने पर कि शिकायत दर्ज करने में लगभग दो साल की देरी हुई थी, एफ. आई. आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया। कि इसके बाद, मूल शिकायतकर्ता ने धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत विद्वान सी. जे. एम. के समक्ष शिकायत/आवेदन दायर किया।

धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन, एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश द्वारा, विद्वान सीजेएम ने धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

6.2 कि आवेदन/शिकायत को खारिज करते हुए, विद्वान सी. जे. एम. ने आरोपों की सच्चाई और सत्यता की पुष्टि की।

मुकूल राय (उपर्युक्त) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर विचार करते हुए, मामले के आरोपों की प्रकृति के अनुसार। विद्वान सीजेएम ने प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी विचार किया। विद्वान सी. जे. एम. द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष और विवादित निर्णय और आदेश द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा मुकेश राय (उपरोक्त) के मामले में लिए गए विचार से सहमत नहीं था और यहां तक कि प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं किया गया था।

और ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बाद, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और कैलाश विजयवर्गीय बनाम को निर्धारित किया है।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या शिकायत/आवेदन में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय व्यक्ति के आयोग का खुलासा करते हैं। अपराध है या नहीं और यदि ऐसा है, तो मजिस्ट्रेट को संबंधित पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करना होगा। कि इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार और रिमांड पर, विद्वान सीजेएम ने सीधे आवेदन/शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसलिए, विद्वान सी. जे. एम. द्वारा पारित बाद का आदेश, विद्वान सी. जे. एम. द्वारा आवेदन/शिकायत को खारिज करने वाले आदेश को रद्द करने और रद्द करने पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक परिणामी आदेश है।

7. अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त की ओर से यह तर्क है कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, मजिस्ट्रेट के लिए आवेदन की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने का अधिकार है।

आरोप, मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और उस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को न्यायिक दिमाग को लागू करना होता है। प्रियंका के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। श्रीवास्तव (ऊपर); मकसूद सैयद (ऊपर); अनिल कुमार (ऊपर); और कृष्ण लाल चावला बनामा उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) में सूचित

5 एस. सी. सी. 435, और साथ ही, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भी, मुकूल राय (ऊपर) के मामले में। अपीलार्थियों की ओर से यह मामला है कि उच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने और/या उसका पालन करने में भौतिक रूप से गलती की है, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में, मजिस्ट्रेट के पास आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उक्त निर्णय उस मामले में लागू नहीं होगा जहां मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय धारा 154 Cr.P.C के तहत पुलिस अधिकारी की शक्तियों पर विचार कर रहा था। और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा [2023] 6 एस. सी. आर. के स्तर पर प्रयोग की गई शक्तियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 156 (3) Cr.P.C को धारा 154 Cr.P.C के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा और/या उनकी बराबरी नहीं की जा सकती है।

8. दूसरी ओर, यह मूल शिकायतकर्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से मामला है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में आदेश दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज करने के चरण में, न तो मजिस्ट्रेट और न ही पुलिस अधिकारी को आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित करने और/या आरोपों की सच्चाई पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र है। प्रत्यर्थियों के अनुसार, उस स्तर पर जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या शिकायत/आवेदन में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सीजेएम

धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में आरोपों की सच्चाई और सत्यता की पुष्टि करना उचित था। और क्या उस स्तर पर मजिस्ट्रेट को न्यायिक दिमाग को लागू करने की आवश्यकता है या नहीं?

9. संविधान का अनुच्छेद 21 पीड़ित और अपराध करने के आरोपी दोनों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

इस कारण से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि कानून का पाठ अन्याय के निवारण और त्वरित, निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रक्रिया का सहारा लेकर अपराध को उजागर करने के लिए जांच करने का अधिकार सुनिश्चित करे। साथ ही, लागू होने वाले कानून को उन मुखबिरो के खिलाफ निर्दोष रक्षा करनी चाहिए जो झूठे आरोप लगाते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं जिससे परेशानी, अपमान और प्रतिष्ठा को नुकसान होता है।

संहिता के अध्याय बारहवें के प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

दंड प्रक्रिया, 1973।

10. धारा 154 से लेकर धारा 176 तक की धारा बारहवें अध्याय की संहिता पुलिस को दी गई जानकारी और जाँच करने की उनकी शक्ति से संबंधित है।

धारा 154 संज्ञेय अपराध करने से संबंधित जानकारी से संबंधित है और प्रथम दृष्टया अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।

एक संज्ञेय अपराध का प्रत्यक्ष अपराध बनाया जाता है। धारा 156 एक पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 156 की उप-धारा (3) में धारा 190 के तहत सशक्त किसी भी मजिस्ट्रेट के लिए धारा 156 (1) में उल्लिखित जांच का आदेश देने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में जहां एक संज्ञेय अपराध किए जाने का संदेह है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजने के बाद

मजिस्ट्रेट को इस तरह के अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है, जिसका हकदार कैलाश विजयवर्गीय बनाम है।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 157 के तहत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना और अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए भी कदम उठाना। खंड (ए) और (बी) धारा 157 की उप-धारा (1) के परंतुक के प्रभारी अधिकारी को किसी मामले की जांच नहीं करने का विवेकाधिकार देते हैं, जब

ऐसा अपराध किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नाम से दिया जाता है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है; या जब यह पुलिस के प्रभारी अधिकारी को दिखाई देता है कि जांच में प्रवेश करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। धारा 157 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, पुलिस के प्रभारी अधिकारी को इसका पालन न करने के कारण बताते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। उप-धारा (1) की अपेक्षाएं और परंतुक के खंड (ख) द्वारा कवर किए गए मामले में, सूचना देने वाले को यह भी सूचित करता है कि वह मामले की जांच नहीं करेगा या इसकी जांच नहीं कराएगा। धारा 159 एक को शक्ति प्रदान करती है

मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने पर, या तो जांच का निर्देश देता है या यदि वह उचित समझता है, तो स्वयं या उसके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, या अन्यथा संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले का निपटारा करता है।

11. धारा 160 से 164 गवाहों की उपस्थिति, गवाहों की परीक्षा, इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता के लिए पुलिस की शक्ति से संबंधित है।

साक्ष्य में बयान, बयान दर्ज करने के लिए प्रलोभन और बयान दर्ज करना। धारा 165 एक पुलिस अधिकारी की जांच के दौरान उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में तलाशी लेने की शक्ति से संबंधित है।

12. संहिता के तहत जांच करने की शक्ति में आम तौर पर निम्नलिखित चरण होते हैं: (क) घटनास्थल की ओर बढ़ना; (ख) तथ्यों का पता लगाना। और मामले की परिस्थितियाँ; (ग) संदिग्ध अपराधी की खोज और गिरफ्तारी; (घ) अपराध करने से संबंधित साक्ष्य का संग्रह, जिसमें व्यक्ति सहित विभिन्न व्यक्तियों की जांच शामिल हो सकती है।

जांच के लिए और मुकदमे के लिए पेश करने के लिए; और (च) इस बारे में राय बनाना कि क्या एकत्र की गई सामग्री पर मामला दर्ज करने के लिए कोई मामला है अभियोजन के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त और यदि ऐसा है तो धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर करके आवश्यक कदम उठाना।

13. धारा 173 में प्रावधान है कि जाँच पूरी की जानी है।

अनावश्यक देरी के बिना और इसे अधिकारी पर अनिवार्य बनाता है पुलिस का प्रभार संबंधित मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजने के लिए जिसमें उसमें प्रदान किए गए तरीके से आवश्यक विवरण हों।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 154 (1) की अनिवार्य प्रकृति।

14. सवाल यह है कि क्या पुलिस धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज करने के लिए बाध्य है।

इस तरह की जानकारी प्राप्त करने या प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने के लिए कुछ अक्षांश होने के कारण, ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में संवैधानिक पीठ का निर्णय हुआ था। इस मामले में, उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि जब कोई निर्दोष व्यक्ति गलत है

आरोपित होने पर, वह मानसिक तनाव, प्रतिष्ठा की हानि का सामना करता है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता गंभीर रूप से बाधित होती है और इसलिए, संहिता की धारा 154 को

संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिदेश के अनुरूप पढ़ा और व्याख्या की जाए। बनाए रखने के लिए नाजुक संतुलन को सुसंगत बनाना

यह राय दी गई थी कि पीड़ित और अभियुक्त के अधिकारों के बीच, एक झूठे मामले के पंजीकरण से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संहिता में ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। हालाँकि, चूंकि धारा 154 का मसौदा पीड़ित के हित और निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच तक पहुँच के उनके अधिकार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, इसलिए धारा 154 के तहत एफ. आई. आर. एस. का अनिवार्य पंजीकरण संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा। पहले के कई निर्णयों और भाषा पर आधारित

लोकतंत्र में। यह पहला कदम है जो पीड़ित को न्याय प्रदान करता है और कानून के शासन को बनाए रखता है, त्वरित जांच की सुविधा प्रदान करता है और कभी-कभी अपराध को रोकने और आपराधिक मामलों में हेरफेर की जांच करता है।

15. संतुलन बनाने के लिए, धारा 41 के तहत एक आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति और संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बीच अंतर किया जाता है। जबकि एक एफ. आई. आर. का पंजीकरण अनिवार्य है, कैलाश विजयवर्गीय बनाम।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

एफ़. आई. आर. दर्ज होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है। एफ़. आई. आर. विश्वसनीय जैसी किसी भी योग्यता के बिना जानकारी के आधार पर दर्ज की जाती है। उचित या सही जानकारी। सूचना की तर्कसंगतता या विश्वसनीयता एफ़. आई. आर. दर्ज करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। हालाँकि, धारा 41 (1) (बी) या (जी) के संदर्भ में गिरफ्तारी करने के लिए, कानूनी आवश्यकताएँ और आदेश 'उचित' अभिव्यक्ति में परिलक्षित होते हैं।

शिकायत 'या' विश्वसनीय जानकारी '।

16. इसके अलावा धारा 154 और 157 के बीच एक अंतर है क्योंकि बाद का प्रावधान धारा के तहत अधिक आवश्यकता का प्रतिपादन करता है।

मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर वह संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करता है। योजना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मजिस्ट्रेट को जांच के सभी चरणों में तस्वीर में रखा जाता है, लेकिन वह वास्तविक जांच में हस्तक्षेप करने या पुलिस को निर्देश देने के लिए अधिकृत नहीं है कि जांच कैसे की जानी चाहिए।

17. ऐसा कहने के बाद, ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले की संवैधानिक पीठ ने, फिर भी, महसूस किया कि न्यायिक व्याख्या द्वारा पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के माध्यम से सुरक्षा की एक और परत तैयार करना आवश्यक था। कुछ मामलों में, अपराधों की उत्पत्ति और नवीनता के कारण प्रारंभिक जांच को उचित ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों की श्रेणी जिसमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, विशुद्ध रूप से उदाहरण के रूप में निम्नलिखित से संबंधित मामलों के रूप में इंगित की गई थी: (क) वैवाहिक/पारिवारिक विवाद; (ख) वाणिज्यिक अपराध; (ग) चिकित्सा लापरवाही के मामले; (घ) भ्रष्टाचार के मामले; या (ङ) ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चन होती हैं,

उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में तीन महीने से अधिक की देरी। उदाहरणात्मक होने का संकेत दिया गया वर्गीकरण उन मामलों का संपूर्ण नहीं है जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। प्रारंभिक जाँच, जब की जानी चाहिए, [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना देरी किए और समयबद्ध तरीके से। जाँच, कारणों और देरी के कारणों को सामान्य डेयरी प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से और सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाना चाहिए। ललिता कुमारी (ऊपर) ने शुरू में कहा था कि प्रारंभिक जांच 7 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जो अवधि कुछ मामलों में अवास्तविक महसूस की गई थी और तदनुसार खंड (vii) 12 नवंबर, 2012 के फैसले को 05 मार्च, 2014 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया गया था:

..... हम अपने निर्णय के अनुच्छेद 111 के खंड (vii) को संशोधित करते हैं।

दिनांक 12 नवंबर, 2013 को निम्नलिखित तरीके से:

" (vii) अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर और असाधारण मामलों में, पर्याप्त कारण देकर, छह सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।

18. पुलिस की जाँच करने की शक्ति और मजिस्ट्रेट को दी गई न्यायिक शक्तियों के बीच अंतर का उल्लेख करते हुए

संहिता का अध्याय बारहवाँ, यह न्यायालय अभिनंदन झा बनाम। ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 117 के दिनेश मिश्रा ने कहा है कि हालांकि मजिस्ट्रेट के पास कुछ पर्यवेक्षी शक्तियां हो सकती हैं, फिर भी, अकेले इन विचारों से वह जांच करने के लिए पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट की शक्ति तब प्रदान की जाती है जब पुलिस द्वारा धारा 157 के संदर्भ में एक रिपोर्ट या धारा 173 (3) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट, जिसके पास जांच में हस्तक्षेप करने की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं है, संहिता की धारा 159 और 173 और धारा 202 के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों को देखते हुए पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है।

संहिता के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति

एफ. आई. आर.

19. इस स्तर पर, एफ. आई. आर. को रद्द करने में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

इस शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब एफ. आई. आर. या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं। इस प्रकार, इन मामलों में, साक्ष्य की सराहना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक अदालत की प्रक्रिया को जारी करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा। लोग।

कैलाच विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

20. एक बार जब किसी अपराध का खुलासा हो जाता है, तो न्याय के हित में अपराध की जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जांच की जरूरत है

प्रकट किए गए अपराध को स्थापित करने या साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से। उचित जाँच के अभाव में जहाँ किसी अपराध का खुलासा किया जाता है, अपराधी उन परिणामों से बचने में सफल हो सकता है जो बड़े पैमाने पर न्याय और समाज के लिए हानिकारक होंगे। अपराध का खुलासा किया जाता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है

अनुमति दी जाए। 21. कानूनी स्थिति का उल्लेख करते हुए, हरियाणा राज्य में यह न्यायालय और अन्य बनाम। भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 ने यह स्पष्ट करते हुए कि यह कोई सटीक सूत्र या एक विस्तृत सूची निर्धारित नहीं कर रहा है, उन मामलों पर प्रकाश डाला जिसमें एक एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है:

" 102. अध्याय 14 के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जो हमारे पास है।

ऊपर निकाले गए और पुनः प्रस्तुत किए गए, हम उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या

अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है

किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्धारित करना

चैनलाइज़्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति हो।

व्यायाम करना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी का गठन नहीं करते हैं।

अपराध करना या अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाना।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एफ. आई. आर. के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, पुलिस [2023] 6 एस. सी. आर. द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता की धारा 156 (1) के तहत अधिकारी कोड।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और

अभियुक्त के खिलाफ मामला।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, एक पुलिस अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

धारा 155 (2) के तहत अनुध्यात मजिस्ट्रेट का आदेश

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है (जिसके तहत -

आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) संस्था के लिए और

कार्यवाहियों की निरंतरता और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो प्रभावी प्रदान करता है।

पीड़ित पक्ष की शिकायत का निवारण।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

श्रीवास्तव (ऊपर), फिर भी ऐसी सीमाएँ हैं जिनके भीतर मजिस्ट्रेट को कार्य करना चाहिए। जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, तो उसे अपना हाथ रखना चाहिए, एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने और आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए इसे जांच एजेंसी पर छोड़ देना चाहिए। मजिस्ट्रेट में ललिता कुमारी (ऊपर) में अनुपात की शर्तें अच्छे कारणों से प्रारंभिक जांच का निर्देश दे सकती हैं। अब हम मजिस्ट्रेट की संज्ञान लेने, प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने और संहिता की धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करने की शक्ति का उल्लेख करेंगे।

कैलाच विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

संहिता की धारा 157 के साथ पठित धारा 154 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने की पुलिस की शक्ति और संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के निर्देश में अंतर। संज्ञान के बाद की शक्ति के विपरीत धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

संहिता की धारा 202 के तहत।

23. संज्ञेय अपराध में सूचना के पंजीकरण और अंतिम जांच के लिए कार्य पुलिस तक ही सीमित नहीं है, और जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 156 की उप-धारा (3), कानूनी शर्तों के अधीन, धारा 190 के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट को सुधार करने की शक्ति देती है।

संज्ञेय अपराध में जाँच का आदेश देना। दो अलग-अलग शक्तियाँ, अर्थात् पुलिस और मजिस्ट्रेट, जो ऊपर बताए गए कोड के तहत अलग-अलग कार्यों और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, पूरी तरह से निहित नहीं हैं।

24. मजिस्ट्रेट की जाँच का निर्देश देने की शक्ति इसके अंतर्गत आती है -

25. रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मजिस्ट्रेट की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की शक्तियों और मजिस्ट्रेट की धारा 202 के तहत आगे बढ़ने की शक्ति के बीच अंतर की जांच की थी। कोड। यह देखा गया कि धारा 190 के तहत संज्ञान लेने से पहले, पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत या पुलिस रिपोर्ट या जानकारी प्राप्त करने पर या उसकी अपनी जानकारी पर, पूर्व धारा के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है। एक बार मजिस्ट्रेट

मजिस्ट्रेट के पास धारा 202 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा लेने का विवेकाधिकार है, जो प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने और मामले की स्वयं जांच करने या पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष जांच का प्रावधान करता है जो यह तय करने के उद्देश्य से उचित समझता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। धारा 202 के परंतुक में कहा गया है कि जांच के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा जहां अदालत द्वारा शिकायत नहीं की गई है, जब तक कि शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों (यदि कोई हो) से धारा 200 के तहत शपथ पर पूछताछ नहीं की जाती है। जब यह मजिस्ट्रेट को दिखाई देता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से [2023] 6 एस. सी. आर. के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्रों में, वह शिकायतकर्ता से अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनसे पूछताछ करने के लिए कहेगा। हालांकि, ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट

अपराध की जाँच के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकते। इस प्रकार, जब लिखित शिकायत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के पास निर्देश जारी करने की शक्ति होती है

धारा 156 (3) के तहत, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले किया जाना है। हालांकि,

दोनों मामलों में, चाहे वह धारा 156 (3) के तहत हो या संहिता की धारा 202 के तहत, अपराधी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही लंबित होती है, तो उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। धारा 203 के तहत, मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता और गवाहों (यदि कोई हो) के शपथ पर बयान और धारा 202 के तहत जांच (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के बाद, शिकायत को खारिज कर सकता है यदि उसकी राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और ऐसे प्रत्येक मामले में अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने के बाद यह राय रखता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह संहिता की धारा 204 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया और तरीके के अनुसार आरोपी को पेश होने के लिए प्रक्रिया जारी करेगा। धारा 204 के तहत अभियुक्त के लिए प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVI के तहत आती है और जारी की जाती है। संहिता की धारा 202 के संदर्भ में एक निजी शिकायत में दर्ज संज्ञान और जांच/जांच/साक्ष्य पोस्ट करें।

26. रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में,

यह जांच करते हुए कि क्या धारा 156 (3) के तहत जांच का निर्देश देने के बजाय धारा 202 के तहत रिपोर्ट बुलाने का मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार किसी भी परिभाषित मापदंडों द्वारा नियंत्रित है, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 22. इस प्रकार, हम पहले प्रश्न का उत्तर यह मानते हुए देते हैं:
22.1 . धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी किया जाना है।

मजिस्ट्रेट द्वारा मन का अनुप्रयोग। जब मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है और प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना आवश्यक नहीं पाता है और तुरंत आगे बढ़ने के लिए एक मामला बनता है, तो उक्त प्रावधान के तहत निर्देश जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता के कारण, या न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए सीधे प्रत्यक्ष जांच करना उचित माना जाता है, तो ऐसा निर्देश जारी किया जाता है।

22.2 . जिन मामलों में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं और प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करते हैं, वे ऐसे मामले हैं जहां मजिस्ट्रेट को अभी तक "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार का अस्तित्व" निर्धारित करना है। श्रेणी

ललिता कुमारी [ललिता कैलाश विजयवर्गीय बनाम] में पैरा 120.6 के तहत आने वाले मामलों की संख्या।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई)

524] धारा 202 के तहत आ सकती है।

22.3 . संहिता की योजना से उपलब्ध इन व्यापक दिशानिर्देशों के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है

एक मामले से दूसरे मामले में न्याय का हित।

धारा 202 के तहत निपटाए जाने वाले मामलों की प्रकृति की व्याख्या करना।

विवेकपूर्ण तरीके से विवेक। यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसके समक्ष लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, तो वह धारा 156 के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेज सकता है और इस तरह मजिस्ट्रेट का मूल्यवान समय जांच में बर्बाद होने से बच सकता है क्योंकि यह मुख्य रूप से पुलिस का कर्तव्य है कि वह जांच करे। हालांकि, मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 202 के तहत संज्ञान लेने और प्रक्रिया का सहारा लेने और प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने की शक्ति भी है, जहां मजिस्ट्रेट ने अभी तक पर्याप्त रूप से अस्तित्व का निर्धारण नहीं किया है। आगे बढ़ने के लिए जमीन। तीसरी श्रेणी के मामलों में, न्यायालय प्राथमिकी का संज्ञान या प्रत्यक्ष पंजीकरण नहीं ले सकता है, लेकिन ललिता कुमारी के मामले (उपरोक्त) में कथन के संदर्भ में प्रारंभिक जांच का निर्देश दे सकता है।

28. प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर) में, इस न्यायालय ने गैर-सैद्धांतिक और विचलित वादियों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला, जो ऐसा करते हैं।

दुर्भावनापूर्ण कारणों से आपराधिक अदालत के दरवाजे पर दस्तक दें। उक्त मामले में उन लोगों द्वारा आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी जिनके खिलाफ वित्तीय संस्थानों ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति व्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई की थी। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 के तहत अधिकारियों को सद्भावना से की गई कार्रवाई के खिलाफ दिए गए संरक्षण के बावजूद था। ललिता कुमारी (उपरोक्त) को दोहराते हुए, यह देखा गया कि धारा [2023] 6 एस. सी. आर. के तहत एक कार्रवाई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

156 (3) शिकायतकर्ता का सहारा लिए बिना उनका मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 154 की उप-धारा (1) और (3) और इन दोनों धाराओं के अनुपालन को आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और आवश्यक होना चाहिए।

कानून का। 29. धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के दायरे के बारे में, यह अदालत मोहम्मद में है। यूसुफ बनाम। अफाक जहां (श्रीमती) और एक अन्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 627 ने कहा कि:

" 11. अतः स्पष्ट स्थिति यह है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने से पहले संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे शिकायतकर्ता से शपथ पर पूछताछ नहीं करनी है क्योंकि वह शपथ नहीं ले रहा था

पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दें। ऐसा करने में कुछ भी अवैध नहीं है। आखिरकार एक एफ. आई. आर. के पंजीकरण में केवल संबंधित जानकारी के सार को दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल होती है संहिता की धारा 154 में बताए अनुसार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में संज्ञेय अपराध करना। भले ही एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का निर्देश देते हुए इतने शब्दों में नहीं कहता है कि एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा प्रकट किए गए संज्ञेय अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करे क्योंकि वह पुलिस अधिकारी संहिता के अध्याय XII में विचार किए गए आगे के कदम उठा सकता है।

उसके बाद ही "। ए. एल. ए. एस. विजयवर्गीय बनाम। राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

30. अंजू चौधरी (ऊपर) में, यह अदालत शक्ति का विश्लेषण कर रही है

धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट ने कहा:

" 41. इस प्रकार, मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत बहुत सीमित शक्ति का प्रयोग करता है और इसी तरह उसका विवेकाधिकार भी है। यह मामले की योग्यता के क्षेत्र में नहीं जाता है यदि ऐसा मामला आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त था। इस अंतर को अदालत द्वारा अलग-अलग मामलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मामलों के प्रकार "।

31. एचडीएफसी सिक्यूरिटीज लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2017) 1 640, यह न्यायालय "संज्ञान ले सकता है" शब्दों की व्याख्या करते हुए

अधिनियम 156 (3), आयोजित किया गया:

" 24. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में एक ऐसे अपराध के होने का खुलासा किया गया है जो प्रकृति में संज्ञेय है और ललिता कुमारी मामले [ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: (2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 524], एफ. आई. आर. का पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। हम.

यह ध्यान रखें कि जिस संदर्भ में वे आते हैं, "संज्ञान ले सकते हैं" शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट है कि इसे "संज्ञान लेना चाहिए" के बराबर नहीं माना जा सकता है। "मई" शब्द इस मामले में मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार देता है। अगर पढ़ने के लिए

शिकायत वह पाता है कि उसमें आरोप एक का खुलासा करते हैं

संज्ञेय अपराध और यह कि धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेजना न्याय के लिए अनुकूल होगा और मजिस्ट्रेट का मूल्यवान समय किसी मामले की जांच में बर्बाद होने से बचेगा, जो मुख्य रूप से पुलिस का कर्तव्य था। यह तय किया जाता है कि जब कोई मजिस्ट्रेट शिकायत प्राप्त करता है, तो वह संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है यदि शिकायत में आरोप लगाए गए तथ्य,

किसी अपराध के होने का खुलासा न करें।

32. हालाँकि, संज्ञान के बाद के चरण में स्थिति अलग होती है।

धारा 202, मजिस्ट्रेट किए गए दोष की सत्यता का विश्लेषण कर सकता है और इस बात की सलाहना कर सकता है कि क्या आगे बढ़ने के लिए आधार हैं। चंद्र देव सिंह बनाम। प्रकाश चंद्र बोस उर्फ चाबी

और एक अन्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1430, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

धारा 202 का अवलोकन करने के लिए:

" 8. मजिस्ट्रेट को इस बारे में राय बनाने में सक्षम बनाने के लिए कि

प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं और [2023] 6 एस. सी. आर. से हटा दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके मन में कोई हिचकिचाहट जो उसने महसूस की होगी

शिकायत का अवलोकन और उस पर विचार

शपथ पर शिकायतकर्ता का साक्ष्य। अदालतों ने इन मामलों में यह भी बताया है कि मजिस्ट्रेट को यह देखना है कि क्या शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में सबूत हैं और क्या सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं। इनमें से कुछ मामलों में विद्वान न्यायाधीशों को यह कहते हुए पीड़ा हुई है कि धारा 202 के तहत जांच की तुलना ऐसे मुकदमे से नहीं की जानी चाहिए जो प्रक्रिया जारी होने के बाद ही हो सकता है और केवल एक ही मुकदमा हो सकता है। निस्संदेह, जैसा कि धारा 202 की उप-धारा (1) में ही कहा गया है, जांच का उद्देश्य शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाना है, लेकिन जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह केवल आंतरिक मामले के संदर्भ में करना है।

जाँच में उसके समक्ष दिए गए बयानों की गुणवत्ता जिसका स्वाभाविक रूप से अर्थ शिकायत ही होगा, शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शपथ पर बयान और शिकायतकर्ता के कहने पर जांच किए गए व्यक्तियों द्वारा उसके समक्ष दिए गए बयान।

33. दूसरी ओर, अभियुक्त के वकील ने शिकायतकर्ता के आचरण पर प्रकाश डाला है, जो प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए विरोधाभासी है।

देरी के लिए स्पष्टीकरण। वह एक डरपोक व्यक्ति और एक अनुभवी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थीं। वह लगातार एफ. आई. आर. एस. दाखिल कर रही हैं। 31 अगस्त 2018 को दर्ज एक प्राथमिकी में, उसने एक तीसरे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था जो उसी में एक राजनीतिक कार्यकर्ता है।

संगठन। 12 दिसंबर 2019 को दायर एक शिकायत में, उसने आरोप लगाया था कि आरोपी पिछले साल चार मौकों पर उससे मिले थे और हर बार उन्होंने मुझे 4 से 5 घंटे के लिए बंद कर दिया था और मामले को वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला था। पुलिस ने 12 दिसंबर 2019 की इस शिकायत पर जांच के बाद 20 दिसंबर 2019 को 2019 की प्राथमिकी संख्या 131 दर्ज की थी और 16 जून 2020 को समापन रिपोर्ट दायर की थी। वास्तव में, मामला बंद कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बाद में 6 फरवरी 2020 को एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कथित बलात्कार की घटना के उस विशेष मामले का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि शिकायतकर्ता द्वारा 12 मार्च 2020 को दर्ज कराई गई शिकायत में भी फिर से कथित बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं था। जवाबी हलफनामे में शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने 29 नवंबर 2018 को बलात्कार की घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

दिन का 11 बजे: 00 बेहाला (महिला) पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल राज्य ने इनकार कर दिया है, जिन्होंने इस अदालत को सूचित किया है कि कोई कैलाश विजयवर्गीय बनाम नहीं है।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

दर्ज की जा रही शिकायत का ऐसा अभिलेख। अभियुक्तों ने 4 अक्टूबर 2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन दायर किया और 22 अक्टूबर 2021 को उनके द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ की प्रतियां प्राप्त की हैं।

पुलिस थाना भवानीपुर दिनांक 30 अक्टूबर 2020 और 5 नवंबर 2020। प्रारंभिक पूछताछ का निष्कर्ष है कि 2018 से 2020 के बीच पुलिस को किए गए संचार में 29 नवंबर 2018 को बलात्कार होने का कोई आरोप नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए कोई तार्किक और संतोषजनक विवरण देने में विफल रहा था। आरोपी का कहना है कि शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और तीसरे व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले को देखते हुए आरोपी पर दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई है।

34. साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता/मुखबिर ने उसके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि के कई आरोप लगाए हैं।

एक महिला के लिए आगे आना और बलात्कार या यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बयान देना मुश्किल है। 35. प्रत्येक आपराधिक मामला, यह कहा जाता है, खोज की एक यात्रा है जिसमें सच्चाई खोज है। न्यायिक प्रणाली की शुरुआत से ही,

यह स्वीकार किया गया है कि सत्य की खोज, पुष्टि और स्थापना न्याय की अदालतों के अस्तित्व में अंतर्निहित प्राथमिक उद्देश्य हैं। हालाँकि, सत्य की सर्वोच्चता को परिभाषित करने की तुलना में दावा करना आसान है। अक्सर यह कार्य मुश्किल हो जाता है जब विरोधाभासी तथ्यात्मक स्थिति होती है।

विधिवत समर्थित होने का दावा किया जाता है और शपथ पर पुष्टि की जाती है। प्रतिकूल प्रणालियों में, सच्चाई का पता लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाओं और साक्ष्य के नियमों के अनुपालन की आवश्यकता होती है, और आरोपों और जवाबी आरोपों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक अन्वेषक के रूप में कार्य करने में न्यायनिर्णायक की भूमिका को सीमित करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि सबूत और सामग्री को संहिताबद्ध प्रक्रियात्मक [2023] 6 एस. सी. आर. के अनुसार रखा और जांच नहीं किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून। फिर भी यह माना जाता है कि तथ्यों को सामने लाने के लिए विरोधियों के टकराव की गणना करना सबसे अच्छा है। एक सुव्यवस्थित प्रणाली में, औपचारिक कानूनी सत्य के न्यायिक निष्कर्ष मूल सत्य के साथ मेल खाना चाहिए। ऐसा हो सकता है।

जब प्रतियोगियों द्वारा बताए गए तथ्यों का कुशलता से पता लगाया जाता है

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। कानून के दुरुपयोग की जांच, यदि संभव हो, तो बहुत हद तक की जानी चाहिए, भले ही यह संभव हो और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भी। वी. आर. कृष्ण अय्यर, जे. ने जसराज इंदर सिंह बनाम में सच्चाई और न्याय की खोज पर प्रक्रिया का सारांश दिया है। हेमराज मुल्तानचंद (1977) 2 एस. सी. सी. 155:

" 8. प्रविष्टियों और प्रति-प्रविष्टियों के तिरछे हिस्से में अटूट रूप से फंसी हुई एक भी वास्तविक वस्तु को चुनना पूरे सत्य के ताने-बाने को फाड़ना था। एक सूक्ष्म अर्थ में, सामंजस्य है

स्वरों के एक पूरे अनुक्रम की सुंदर समग्रता और मधुर ध्वनियों की एकरूपता असंबद्ध कलह में परिवर्तित हो जाती है यदि एक या दो स्वरों को संगीत के बिना काटा और बजाया जाता है। सत्य, गीत की तरह, संपूर्ण है और आधा सत्य शोर हो सकता है; न्याय सत्य है, सौंदर्य है और अन्याय को ठीक करने की रणनीति संपूर्ण सत्य की खोज और मानव संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना है। कानून का सबसे अच्छा समय अमूर्तता पर ध्यान देने में नहीं है, बल्कि पूर्ण निष्पक्षता के वितरण एजेंट होने में है। इस विभाजन को खुद को यह याद दिलाने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया जाता है कि कानून के अनुसार न्याय का व्याकरण कोई छोटा कानूनी समाधान नहीं है।

अलग-अलग समस्याओं का लेकिन संघर्ष को इसके व्यापक असर में हल करना।

36. पश्चिम बंगाल राज्य ने गोपाल दास सिंधी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। की स्थिति

असम और एक अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 986 इस प्रभाव से कि जब कोई निजी शिकायत दायर की जाती है, तब भी मजिस्ट्रेट धारा 190 के तहत संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसमें इस्तेमाल किया गया शब्द 'मई' है, जिसे स्पष्ट कारणों से 'जरूरी' नहीं माना जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट ठीक हो सकता है

धारा 156 (3) के तहत ऐसी शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजने में विवेक का प्रयोग करें। हालाँकि, जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आगे नहीं बढ़ने का विकल्प चुनता है, तो वह केवल शिकायत को खारिज नहीं कर सकता है यदि उसे लगता है कि धारा 156 (3) का सहारा लेना उचित नहीं है। इस संबंध में सुरेश चंद जैन बनाम का भी उल्लेख किया जा सकता है। एम. पी. राज्य और दूसरा, (2001) 2 एस. सी. सी. 628 जो धारा 156 के तहत जांच करने की पुलिस की शक्ति के बीच अंतर करता है,

धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए मजिस्ट्रेट और संहिता की धारा 190 और धारा 202 के तहत संज्ञान के बाद समन के बाद जांच और जांच। जब कोई मजिस्ट्रेट धारा कैलाश विजयवर्गीय V के तहत जांच का आदेश देता है।

राजलक्ष्मी चौधरी और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

156 (3) , वह अपराध का संज्ञान लेने से पहले ऐसा करता है। यदि वह संज्ञान लेता है, तो उसे अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है (देखें अफाक जहां (ऊपर)।

मोना पंवार बनाम में निर्णय। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय अपने पंजीयक और अन्य के माध्यम से, (2011) 3 एस. सी. सी. 496 है

बल्कि संक्षिप्त। इस न्यायालय ने कहा कि जब कोई शिकायत प्रस्तुत की जाती है

मजिस्ट्रेट के सामने उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक धारा 156 (3) द्वारा अनुध्यात आदेश पारित करना है। दूसरा शपथ पर शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाह की जांच का निर्देश देना है, और धारा 202 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से आगे बढ़ना है। धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पुलिस को एक आकस्मिक अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति में है धारा 156 (1) के तहत जांच की अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करें। हालांकि, एक बार जब मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान ले लिया है, तो वह पुलिस से जांच के लिए नहीं कह सकता है। संज्ञान लिए जाने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट कोई जांच चाहता है, तो यह धारा 202 के तहत होगा, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है और किसी झूठी या परेशान करने वाली शिकायत में प्रक्रिया को जारी करने से रोकना है। इसलिए इस तरह की जांच यह पता लगाने के लिए प्रदान की जाती है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

37. हम आरोपों के गुण-दोष के सवाल में नहीं जाना चाहते हैं, और मजिस्ट्रेट को किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए क्योंकि यह है एक पहलू जिस पर मजिस्ट्रेट को पहले विवेकपूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। जो अस्वीकार्य और कानून के विपरीत है, वह आरोपों के गुण-दोष और तथ्यों के निर्धारण पर निर्णय है।

बिना आगे की जांच और जांच के आधारहीन। इसलिए, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजने में सही किया।

38. हमें सूचित किया गया कि मजिस्ट्रेट, रिमांड पर, गुजर चुके हैं

धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और निर्देशों को गलत पढ़ा है। इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में, मजिस्ट्रेट से जांच करने, अपने विवेकपूर्ण दिमाग को लागू करने और फिर विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है कि वह धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करे या नहीं या क्या उसे संज्ञान लेना चाहिए और धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वह ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकता है।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. हम टालेंगे और लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

क्योंकि यह दोनों पक्षों द्वारा रखे गए मामले को प्रभावित कर सकता है। अभियुक्त को समन जारी होने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, कानून उन्हें कार्यवाही में पुनरीक्षण अदालत के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार देता है, जब शिकायतकर्ता संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देता है। इसलिए, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए और कार्यवाही का विरोध किया। उन्होंने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कई कागजात और दस्तावेज दायर किए हैं। उनके लिए निष्पक्ष होने के लिए, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए कागजातों और दस्तावेजों की प्रतियां भी भेजी जाएंगी और मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में रखी जाएंगी, जो इसके बाद मामले की जांच और विचार करेंगे। हालाँकि, शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता और सामग्री पर सवाल उठाने का अधिकार होगा।

40. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए

मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के अनुसरण में मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड पर पारित बाद के आदेश को दरकिनार कर देते हैं और मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक दिमाग की जांच करने और लागू करने के लिए वापस भेजते हैं और फिर विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं कि धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करना है या नहीं या क्या वह संज्ञान ले सकता है और धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन कर सकता है। वह ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकता है। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए कागजातों और दस्तावेजों की प्रतियां भी भेजी जा सकती हैं और मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में लाई जा सकती हैं, जो इसके बाद मामले की जांच और विचार करेंगे। जैसा कि ऊपर देखा गया है, शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को उक्त दस्तावेजों की सामग्री की वास्तविकता पर सवाल उठाने का अधिकार होगा।

41. वर्तमान अपीलों का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है।

निधि जैन

अपी

लों का निपटारा किया गया।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)